(ख) क्या उपरोक्त खर्च संतुलित तरीके से किया जा रहा है, यदि नही, तो क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय हित में इस अनुचित झुकाव को ठीक करने का है, यदि हां, तो कैसे ; और

(ग) सरकार को लिक्षा शुल्क से कुल कितनी आय होती है और क्या जिस वर्ग से शिक्षा शुल्क लिया जाता है, उस वर्ग पर पर उसी अनुपात में खर्च किया जाता है।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रकाश चन्द्र चन्द्र) : (क) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और केन्द्र के संबंध में प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा पर 1976–77 राजस्व खाते के लिए बजट में रखा गया व्यय इस प्रकार है :—

(रुपय हजारों में)

प्राथमिक शिक्षा	8660650
माध्यमिक शिक्षा	5800512
उच्च शिक्षा (तकनीकी तथा विश्वविद्यालय और अनुसंधान सहित)	3665395

(ख) राज्य अपनी अपनी निजी व्यय पद्धतियों का निर्णय अपनी अपनी आवश्यकताओं के आधार पर करते हैं ।

(ग) शिक्षा पर कोई केन्द्रीय उपकर नहीं है ।

मध्य प्रदेश में सघन भेड़ विकास कार्यक्रम

4650. **श्री लक्ष्मी नारायण नायक** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सघन भेड़ विकास कार्यक्रम के लिय मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों का चयन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए तैयार किये गय कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इस कार्यक्रम में बकरियों के विकास को भी शामिल किया गया है ; और

(घ) यह कार्यक्रम कब आरम्भ किया गया था और इस के लिय वार्षिक अनुमानत: कितनी धन राशि मंजूर की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

Water Rates charged by DDA in Rajauri Garlen, D. D. A. Colonies

4651. SHRI JAGANNATH SHARMA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the water rates charged by the DDA in the Rajauri Garden (G-8 Area) DDA colonies;

(b) whether these rates are four times more than the rates charged by the Delhi Municipal Corporation;

(c) the reasons for these enhanced rates;

(d) whether the Welfare Agencies of these colonies had met the Vice-Chairman and whether he assured them that these rates would be reduced with retrospective effect; and

(e) if so, whether Government have asked the authorities not to harass the residents till a final decision is taken?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) The Delhi Development Authority is charging 70 paise per

kilo litre for metered water supply and Rs. 20 per month per flat for unmetered water supply with effect from 1st October, 1976.

(b) and (c). No, Sir. However, recently the Municipal Corporation, Delhi has reduced the charges for bulk supply of water and a corresponding reduction will also be made by Delhi Development Authority.

(d) Delhi Development Authority has reported that it is not aware of any such assurance.

(e) Does not arise.

मरु-भूमि को उपजाऊ भूमि में बदलना

4852. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि को बढ़ावा देने हेतु ऊसर और मरु भूमि को कृषि भूमि में बदलने का कोई कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष में इस बारे में कितना व्यय किया जायेगा ; और

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी ऊसर और मरुभूमि को कृषि योग्य भूमि में बदला जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां । सरकार ने देश में कृषि को बढ़ावा देने की दृष्टि से बंजर और मरु भूमि का सुधार करके उन में खेती करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए हैं :—

1. राजस्थान में थार मरुस्थल के एक बड़े भाग में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाई गई राजस्थान नहर परियोजना जिससे मरु क्षेत्र को कृषि उत्पादन के लिए सुधारने में मदद मिलेगी । हरियाणा और गुजरात की कुछ सिंचाई योजनाओं से भी इन राज्यों के मरु क्षेत्रों के कुछ भागों में सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध होंगी ।

2. राजस्थान नहर क्षेत्र में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई क्षेत्र विकास और कृषि संबंधी सहायक सेवाओं के उचित उपयोग द्वारा कृषिहेतु मरुभूमि का विकास किया जा रहा है । वन रोपण, आश्रय पट्टियां लगाने, चरागहों के विकास और ईंधन हेतु वृक्षारोपण संबंधी कार्य भी किए जा रहे हैं ।

3. सूखे से प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम राजस्थान के 9 मरु जिलों में, गुजरात के 2 मरु जिलों के कुछ भागों में और हरियाणा के 2 मरु जिलों में चल रहा है । इस योजना के अन्तर्गत मृदा संरक्षण उपायों से कृषि भूमि के उपचार, सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने, वनारोपण, चरागाह विकास आदि के लिए एक समेकित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है ।

4. इन क्षेत्रों में परिस्थितिक संतुलन कायम करने तथा उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से वर्तमान सरकार ने चालू वर्ष में मरु विकास की एक योजना शुरू की है । इस कार्यक्रम में लघु और सीमांत कृषकों तथा कृषि श्रमिकों की आय और रोजगार का स्तर बढ़ाने के बारे में भी विचार किया गया है ।

5. उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्यों में अल्काली (ऊसर)